

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बहुजलास डॉ० अमित यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या -148/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर - 2022/178

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोंडेन्ट्स
सहीराम विश्नाई पुत्र खीयाराम जाति विशनाई निवासी 170, संजय कॉलोनी, नागौर तहसील व जिला नागौर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर 2. पटयारी हल्का नागौर जिला नागौर

उपस्थिति:-

1. अपीलान्त की ओर से वकील श्री सोहनलाल लटियाल।
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

:: निर्णय ::

दिनांक :- 22.08.2023

अपीलान्त द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 12/2022 सरकार बनाम सहीराम में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.05.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्त की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्त ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ-पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्त ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.03.2022 को जारी कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलांत को नहीं थी। दिनांक 08.03.2022 को अपीलांत पेशी पर उपस्थित था तथा अपना जवाब मय दस्तावेजात प्रस्तुत किया। तब अदालत मातहत ने कहा कि इसमें मौके पर जांच करेंगे व नाप चौप भी करवायेंगे, जिसकी जानकारी दे दी जायेगी, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर कोई जांच नहीं की तथा न ही अपीलांत को तारीख पेशी 21.03.2022 को होना बताया तथा बिना अपीलांत को सूचना दिये, बिना सुनवाई किये अपने मनमाने तरीके से तारीख 21.03.2022 की पेशी दर्ज कर निर्णय जेर अपील आदेश पारित कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलांत को दिनांक 29.04.2022 को मामला हाजा में जांच करने हेतु मौका पर आने एवं जानकारी करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में गया तो बताया गया कि मामले में तो दिनांक 21.03.2022 को ही पत्रावली का निर्णय कर दिया गया है, तब अपीलांत ने उसी वक्त आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया, जिस पर नकल प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश जेर अपील की दिनांक 02.05.2022 को प्राप्त हुई। इसके उपरांत अपीलांत को अपनी राजकीय सेवा से अवकाश नहीं मिला। जिससे अधिवक्ता से सम्पर्क कर कानूनी जानकारी लेकर यह अपील पेश की है। अपील अपीलांत की जानकारी से अंदर मियाद है। अतः आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांत अन्दर मियाद में शुमार की जावें।



2
कलक्टर नागौर

राजकीय पैरोकार ने मियाद के बिन्दू पर यह कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 21.03.2023 को होते हुवे भी यह विलम्ब से अपील पेश की गई है। अपील मयाद बाहर होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट नम्बर 1 ने दिनांक 01.02.2022 का नोटिस दिया कि कृषि वर्ष 2078 के दौरान नागौर तहसील के ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 267 गैर मुमकिन तालाब क्षेत्रफल 1352 वर्गफुट पर अपीलांट ने कब्जा किया है, जिसका जवाब अपीलांट ने दिनांक 08.03.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है। प्रकरण के सही तथ्य यह है कि मुझ अपीलांट का प्लोट नम्बर 170 का पूर्वी आधा भाग 1345.5 वर्गफुट है, जिसमे अप्रार्थी का पूरा मकान बना हुआ है। नगरपालिका मण्डल नागौर द्वारा राजस्थान सरकार का सन 1975 में प्लॉन बनाया जाकर विकसित व नगरपालिका नागौर द्वारा सन 1984-85 में विक्रय की गई संजय कॉलोनी नागौर की आबादी भूमि खसरा नम्बर 255 में स्थित प्लोट नम्बर 170 का आधा भाग मेरे स्वामित्व की जायगा में है। प्लोट नम्बर 170 जिसका कुल एरिया 2891 वर्गफुट है, जो मेरे नाम से दिनांक 26.02.1993 को लीज डीड जारी की गई, जिसका आधा भाग मुझ अपीलांट द्वारा दिनांक 09.04.2018 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के आधा पश्चिमी हिस्सा सुरेश विश्नोई को विक्रय किया गया तथा आधा पूर्वी हिस्सा में मुझ अपीलांट ने दिनांक 06.11.2019 को नगरपालिका मण्डल नागौर से भवन निर्माण स्वीकृती प्राप्त कर भवन का निर्माण करवाया तथा परिवार सहित निवास करता है। भूखण्ड संख्या 170 के पश्चिम में नगरपालिका का भूखण्ड संख्या 171 है तथा उसके दक्षिण में नगरपालिका की 40 फुट की रोड है तथा उसके दक्षिण-पश्चिम में नगरपालिका का सार्वजनिक पार्क है, जिसमे सन 1986-87 से पीएचईडी द्वारा खोदा गया हेण्ड पम्प है, जो पार्क की बनी हुई चार दीवारी के अंदर पश्चिम की तरफ है तथा पूर्व में सन 1989-90 में पटवारी हल्का लालसिंह व आरआई गंगाधर द्वारा मौके का माप किया गया था, तब यह बताया गया था कि हेण्ड पम्प पर खसरा नम्बर 267 का पूर्वी दक्षिणी छोर स्थित है, जो सेटलमेन्ट के राजस्व नक्शा शीट से भी स्पष्ट है। मौका पर बिना माप किये मनमाने तरीके से पटवारी ने गलत रिपोर्ट देकर अपीलांट के मकान को खसरा नम्बर 267 में गलत रूप से बताया जा रहा है, जो सरासर अन्याय है। अपीलांट का मकान खसरा नम्बर 267 में कतई नहीं है, असल नक्शा शीट से नक्शा ट्रेस कर मुकमिल पाइंट से नाप करवाया जावे। मुकमिल पाइंट जैन सरावगियो के श्मशान की भूमि खसरा नम्बर 270 के पश्चिम की तरफ प्राचीन दीवार सेटलमेन्ट के पहले से बनी हुई है तथा पूर्व में रेल्वे लाईन का पूर्वी छोर सेटलमेन्ट से पूर्व का स्थित है, जो मुकमिल बिन्दू दोनो तरफ शुरु की स्थिति में ही कायम है तथा दोनों के बीच संयुक्त रूप से माप आसानी से किया जा सकता है। जिस पर सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। अपीलांट सहीराम विश्नोई के वैधानिक सही स्वामित्व का प्लोट नम्बर 170 नगरपालिका मण्डल नागौर द्वारा विकसित व विक्रय की गई संजय कॉलोनी नागौर में स्थित है। राजकीय भूमि पर किसी भी तरह से कोई अतिचार एक इंच भूमि पर भी नहीं किया गया है। जिसके सम्पूर्ण दस्तावेज की फोटो प्रति साथ पेश है। यह है कि नगर पालिका मण्डल नागौर द्वारा योजना बनाकर राज्य सरकार से राजस्व भूमि अपने कब्जे में लेकर नागौर रेल्वे लाईन के पश्चिम की तरफ खसरा नम्बर 255, 261, 266, 267 के भू भाग पर टाउन प्लानर द्वारा प्लान नक्शा बनाया गया, जो नगरपालिका नागौर, जिला प्रशासन नागौर व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया, तत्पश्चात नगरपालिका नागौर के हक में उक्त भूमि



को आबादी में अलग अलग लोगो को भूखण्ड सन 1984-85 में विक्रय किये, तब से सम्पूर्ण कॉलोनी में आबादी वैधानिक रूप से बसी हुई है। नगरपालिका नागौर के स्वीकृत नक्शा अनुसार की संजय कॉलोनी का पार्क नगरपालिका नागौर द्वारा बाउण्ड्री बनाकर विकसित किया गया, जिसमे राधाकृष्ण मंदिर भी बना हुआ है, पीएचईडी की पानी की टंकी बनी हुई है तथा प्राथमिक विद्यालय प्लान अनुसार सन 2000 में राज्य सरकार द्वारा बनाया गया, जहां वर्तमान में जिला प्रशासन व सीएमएचओ नागौर व नगर परिषद द्वारा स्वीकृत जनता क्लीनिक चल रहा है। इस प्रकार सम्पूर्ण कॉलोनी प्लान अनुसार बसी हुई विकसित हुई है। मौका पर संजय कॉलोनी प्लान की भूमि पर व आसपास कभी कोई तालाब नहीं रहा है तथा न है तथा न ही कोई अंगोर की भूमि है। फिर भी इन तथ्यो, परिस्थितियो, साक्ष्य, रेकर्ड व दस्तावेजो के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने कार्यवाही हाजा में नगरपालिका नागौर द्वारा जारी दस्तावेजो में किसी खसरे का उल्लेख नहीं होने का उल्लेख नहीं होना, पूर्व राजस्व अधिकारियो द्वारा अनापति में भी खसरे का उल्लेख नहीं होने व गैरमुमकिन तालाब की भूमि होने व इस प्रकार उक्त भूमि को धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित मानकर अपीलांट के विरुद्ध बेदखली व जुर्माना रूपये 5 का आदेश जेर अपील पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत व दस्तावेजो व मौके की स्थिति के विपरीत होने से अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 21.03.2022 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली देखने से भी स्पष्ट है कि पटवारी रिपोर्ट के पिछले पृष्ठ पर अपीलांट को अतिचारी बताने के लिए एक नक्शा बनाया गया है। उसमे भी न तो पडोस अंकित किये हैं, न किसी भी तरह का नाप चौप अंकित किया है तथा अपने मनमाने तरीके से लाईने खींचकर अपीलांट को अतिचारी दर्शित कर दिया तथा न ही पटवारी मौके पर गया, अगर पटवारी हल्का मौके पर जाता तो मौके की स्थिति पर अपीलांट के मकान के चारो तरफ नगरपालिका की विकसित व विक्रय की गई संजय कॉलोनी नागौर की पूरी आबादी सन 1984-85 से बसी हुई है, उसका ज्ञान होता व रिपोर्ट में मौके की सही स्थिति दर्शित होती। जिसका अपीलांट के जवाब में पूर्ण विवरण व दस्तावेज पेश किये हुए थे। जिनका विवरण भी अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं दिया, न देखे। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जेर अपील न्यायालय के सामान्य सिद्धान्तो के व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरुद्ध बिना जांच किये होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अत्यन्त ही जल्दी एवं हड़बड़ी रखते हुए निर्णय पारित किया है क्योंकि वर्तमान प्रकरण में न तो अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया व न ही अपीलांट के जवाब का आदेश जेर अपील में विवरण दिया गया, मात्र जल्दबाजी पूर्वक अपीलांट को बेदखली करने के उद्देश्य यह निर्णय जेर अपील पारित किया है, जिससे भी आदेश जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक साइक्लो स्टार्डिल निर्णय है, यह निर्णय पूर्व में ही टाईप किया हुआ है, इसमे मात्र खाली स्थानो की पूर्ति के लिए नाम व खसरा नम्बर व जुर्माने का अंकन किया गया है, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूर्व में ही बेदखली का निर्णय पारित किया गया है तथा अपनी कार्यवाहियो के टारगेट की रिकार्ड में पूर्ति के लिए यह निर्णय जेर अपील के नाम पर खानापूर्ति की गई है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व आदेश दिनांक 21.03.2022 में अधीनस्थ न्यायालय ने लिखा है कि "केवल सीमा ज्ञान ही एक ऐसा आधार



हे कि उक्त व्यक्ति का कब्जा/अतिक्रमण गैर मुमकिन तालाब पर है अथवा नहीं, अतः पत्रावली निर्णय इस अनुसार की जाती है कि पटवारी हल्का एक बार पुनः सीमा ज्ञान वक्त बेवखली की कार्यवाही कर ले एवं यदि कब्जा तालाब की भूमि पर है तो अप्राप्ती द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राजस्थान सरकार द्वारा दर्ज तालाब की भूमि पर लागू नहीं हैं, अतः बेवखल कर दिया जावे।" इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के सामने अपीलान्ट का अतिक्रमण है या नहीं, इस संबंध में कोई भी स्पष्ट रिपोर्ट नहीं थी तथा जो पटवारी हल्का अपने चाहे तरीके से एक झुठी व गलत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के सम्मक्ष पेश कर दी, उसी को मानकर तथा उसे ही उसके संबंध में तय करने के लिए अधिकृत कर दिया। जो भी न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत है कि शिकायतकर्ता को ही जज बना दिया गया। जो कतई विधि सम्मत नहीं होने से आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है तथा आदेश जैर अपील अपने आप में निर्णय की तारीफ में भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करना बताकर निर्णय जैर अपील पारित किया है। जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से अधीनस्थ न्यायालय के सम्मक्ष स्पष्ट था कि अपीलान्ट को जिस भूमि पर अतिचारी बताया जा रहा है, उक्त भूमि नगर परिषद नागौर के कब्जे की भूमि है, जहां नगर परिषद नागौर ने जिला प्रशासन व टाउन प्लानर व राज्य सरकार की सहमति से उक्त भूमि पर नगर परिषद नागौर ने कब्जा प्राप्त कर अलग-अलग लोगों को भूमि विक्रय कर प्लान अनुसार अलग-अलग लोगों को स्वीकृती दी गई व प्लान अनुसार ही लोगों ने मकान बनाये तथा वैधानिक लीज डीडधारी लोगों ने अपने भवन बनाये, जिससे अपीलान्ट किसी भी प्रकार से अतिचारी की तारीफ में नहीं आता। अगर उक्त भूमि किसी कारण से आज भी राजकीय भूमि दर्ज रह जाने में अपीलान्ट की कोई गलती नहीं है। राज्य कर्मचारियों की गलती, सजा अपीलान्ट को किसी भी तरीके से नहीं दी जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय जैर अपील खारिज किया जायें।

राजकीय पैरोकार ने अपनी बहस में यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया तथा निर्णय भी विधिवत पारित किया गया है। अपीलान्ट स्वयं ने सीमा ज्ञान करवाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकरण में पुनः दिनांक 12.03.23 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है तथा टीम द्वारा किये गये सीमाज्ञान में अपीलान्ट का कब्जा व मकान तालाब की भूमि पर पाया गया है। इसलिए पटवारी द्वारा इस प्रकरण में रिपोर्ट सही पेश की गई है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी निर्णय सही पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है, इसलिए अपीलान्ट अपील खारिज फरमायी जायें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से यह प्रकट है कि पटवारी हल्का, नागौर एवं निरीक्षक(भू0अभिलेख), नागौर द्वारा दिनांक 31.01.2022 को इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 267 रकबा 1352 गै0मु0 तालाब पर सहीराम पुत्र खीयाराम कौम विश्वाई नियासी भेड़, तह0खीयसर द्वारा सम्बत् 2078 में जयिमे पक्का मकान रहवासी के नाजायज कब्जा कर लिया है। इस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, नागौर द्वारा प्रकरण 12/2022 विरुद्ध श्री सहीराम के दफा 91 आर.एल.आर.एक्ट. दर्ज किया गया तथा इस प्रकरण में दिनांक 21.03.2022 को निर्णय पारित करते हुवे अपीलान्ट को भू0अभिलेख निरीक्षक व पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना जाकर भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दोषी मानकर मौके पर से भौतिक रूप से बेवखल करने का आदेश दिया है।

पत्रावली के संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गैर सायल द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों का अलगाव एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत फोटो प्रति



लीज लीड पत्रावली संख्या 52/85-86 के अवलोकन से प्लॉट संख्या 170 क्षेत्रफल 39X69 दिनांक 26.02.1983 को 99 वर्ष लीज पर श्री सहीराम को दिया गया है। उपरोक्त दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह प्रकट है कि भूखण्ड संख्या 170 नगरपालिका द्वारा सहीराम को आवंटन/लीज पर दिया गया है। तथा उसने उक्त प्लॉट का पश्चिमी भाग सुरेश को जरिये विक्रय पत्र विक्रय कर दिया है। अब इस प्रकरण में मुख्य बिन्दू यह रहता है कि यह प्लॉट स्थित कहाँ है। क्योंकि तहसीलदार, नागौर द्वारा इस प्लॉट को गै0मु0 तालाब की भूमि में माना है, जबकि नगरपालिका द्वारा आबादी भूमि मानते हुये लीज पर दिया गया है। हालांकि इस प्रकरण में तहसीलदार, नागौर के निर्णय के बाद तहसीलदार द्वारा सीमांकन करवाया गया जो फर्द सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 12.03.2023 की फोटो प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, उसके साथ जो साईट प्लान पेश किया है, उसके अवलोकन से यह प्रकट है कि भू खण्ड संख्या 170 खसरा नम्बर 267 व खसरा नम्बर 255 की लगती सीमा पर है, इसलिए इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तय किया जाना है कि प्रश्नगत भूमि नगरपालिका को आबादी हेतु दी गई भूमि का भाग है या फिर गै0मु0 तालाब की भूमि है। इस प्रकार का अंकन तहसीलदार, नागौर ने भी अपने निर्णय दिनांक 21.03.2022 में किया है। इस बिन्दू को तय करने हेतु तहसीलदार, नागौर को नगरपालिका, नागौर को आबादी हेतु सुपुर्द की गई भूमि का राजस्व रेकार्ड/राजस्व नक्शा एवं नगरपालिका द्वारा बनायी गई कॉलोनी का साईट प्लान, उसका क्षेत्रफल आदि की स्थिति का आंकलन किया जाना है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नागौर का जैर अपील आदेश दिनांक 21.03.2022 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार, नागौर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये नगरपरिषद्, नागौर की टीम एवं राजस्व विभाग की टीम के सहयोग से प्रश्नगत भूमि की सही स्थिति का आंकलन करते हुए व अप्रार्थी को विधिवत सुनवाई, साक्ष्य, सबूत आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सीरे से निर्णय पारित करे। साथ ही अपीलान्ट को भी यह निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 20.09.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुये निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।



(डॉ० अमित यादव)
जिला कलेक्टर, नागौर
कलेक्टर नागौर